है । राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, फलों के फलों पर आधारित पेय पदार्थों का विपणन करने के लिये जूस वेन्डिंग मशीन लगाने के लिये सहायता देता है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित कर रहा है :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य, फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग सुविधायें का विकास करने के लिये योजनायें ;

(2) खाद्य, फल और सब्जियों की प्रोसेसिंग सुविधाओं को स्थापित करने अथवा उनका विस्तार करने के लिये राज्य सरकार के उपक्रमों और राज्य स्तर को सहकारी समितियों को सहायता देने के लिये योजनायें ।

(3) खुम्बी (मशरूम) की खेती करने व इसकी प्रोसेसिंग करने के लिये अवसंरचना का विकास ।

(4) मुख्य हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और उत्पादकता केन्द्रों में प्रशीतनगृह (कोल्ड स्टोरेज) सुविधाओं का विकास ।

Use of balanced fertilisers

2524. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have formulated plans to promote use of balanced fertilizers of different kinds; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) and (b) A scheme for promoting the balanced and Integrated Use of Fertilizer, to be implemented by the Fertilizer Industry with 50 per cent central assistance has been prepared. The scheme has provision for Input Diagnostic Centres, Mobile Soil Testing Vans and Demonstration on Micronutrient Use.

Use of Fertilizer in the Country

2525. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state what is the recommended quantity of fertilizer of different kinds to be used in different States and areas of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): The fertilizer recommendations are generally expressed in terms of Kilo Grams of nutrients *i.e.* Nitrogen, Phosphorus and Potassium per hectare. These recommendations are based on the type of soil and its fertility status, crop and its variety, availability of irrigation and targetted levels of crop yields. General recommendations are made by the State Governments in consultation with their Agricultural Universities. The State-wise recommendations are modified by the District level agricultural authorities, which may be valid for the concerned districts.

In view of the above consideration, the crop-wise recommendations vary greatly. The range of Niterogen, phosphorus and potassium being recommended for some of the important crops are enclosed in the Statement.

Statement

Fertilizer Recommendacion for some Majo r Crops (Range)

Crop	Kg. per ha.		
	Nitrogen	Phos-phorus	Potta-sium
Paddy	30—130	15—60	0.60
Wheat	30—130	20—62·5	0·62.5
Cotton	50—162	25—125	25—80
Sugarcane	100—400	35—170	20—170
Maize	30—140	15—45	0
Jowar	20—90	10—50	0
Groundnut	10—32	20—65	—

"ग्रापरेशन फ्लड प्रोग्राम" की पुनरीक्षा

2525. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "ग्रापरेशन फ्लड प्रोग्राम" की पुनरीक्षा की है ;

(ख) क्या यह सच है कि लगभग सभी दुग्ध संघों/सहकारी संस्थाग्रों को भारी हानि हो रही है ;

(ग) क्या पशुधन ग्रौर डैरी विकास से संबंधित कार्यकारी दल ने सिफारिश की थी कि ग्राठवीं पचवर्षीय योजना में दुग्ध संघों की संचित हानि को प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार को 50–50 प्रतिशत के ग्राधार पर करनी चाहिए ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपर्युक्त सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) ग्रापरेशन फ्लड-3 की प्रगति की मानिटरिंग इस प्रयोजन के लिये गठित की गई संचालन समिति द्वारा की जा रही है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है ग्रौर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) परिसंघों/संघों की पिछली संचित हानि को बट्टे खाते में डालने की एक योजना ग्राठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में शामिल की गई है ।

Cyclone and Floods in Mizoram

2527. SHRI HIPHEI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the assistance provided so far by the Central Government to Mizoram to meet the situation arising out of cyclone and floods in the State last year; and

(b) the nature of assistance likely to be provided to Mizoram during 1992-93?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) During 1991-92, Central Government has released an amount of Rs. 75.00 lakhs as the